नवरात्र बाद ४.५० लाख पेंशनर्स के हित में होगा आंदोलन

५९ माह के एरियर्स पर पेंशनर्स में नाराजगी
कैशलेस इलाज और जनवरी २०२६ से २ प्रतिशत महंगाई राहत की भी मांग

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश में ५९ माह के बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग को लेकर पेंशनर्स का असंतोष बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नवरात्रि के बाद मंत्रालय के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि छठवें और सातवें वेतनमान के ५९ माह के एरियर्स, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और लंबित महंगाई राहत का भुगतान नहीं होने से प्रदेश के करीब ४.५० लाख पेंशनर्स प्रभावित हैं। शिवाजी नगर में हुई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की भोपाल जिला शाखा की बैठक में लंबित मांगों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलेभर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए।

बैठक में पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि लंबित मांगों के निराकरण में शासन की ओर से लगातार देरी की जा रही है। संगठन के मुताबिक ५९ माह के एरियर्स का भुगतान किए जाने के बजाय इस मामले में कोर्ट से स्टे लेने के निर्देश की जानकारी सामने आने के बाद पेंशनर्स में नाराजगी और बढ़ी है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से छठवें और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए।

कैशलेस इलाज और २ प्रतिशत महंगाई राहत भी मुद्दा

पेंशनर्स ने केवल एरियर्स ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग भी दोहराई। इसके अलावा जनवरी २०२६ से लंबित २ प्रतिशत महंगाई राहत जारी करने की मांग की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि उम्रदराज पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का खर्च लगातार बड़ी चिंता बनता जा रहा है। ऐसे में कैशलेस उपचार की सुविधा से उन्हें सीधे राहत मिल सकती है।

नवरात्रि बाद मंत्रालय के सामने प्रदर्शन

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो नवरात्रि पर्व के बाद भोपाल में मंत्रालय के समक्ष व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी पेंशनर्स के हित में लंबित मांगों पर निर्णय लेने का आग्रह करेगा। बैठक में मौजूद पेंशनर्स ने आंदोलन में संगठन का सहयोग करने और अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का संकल्प लिया।

वामा साहित्य मंच की मासिक बैठक कल

इन्दौर (ईएमएस) होटल अपना एवेन्यू में आज २ अक्टूबर को वामा साहित्य मंच की मासिक साहित्यिक बैठक दो दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में साहित्यप्रेमी और रचनाकार शामिल होंगे। अक्टूबर माह की इस बैठक का विषय हाइकु विधा रहेगा। इसमें साहित्यकार हाइकु के माध्यम से कम शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। अध्यक्ष ज्योति जैन, संयोजक विनीता शर्मा, रश्मि स्थापक और सचिव स्मृति आदित्य ने बताया कि बैठक के मुख्य अतिथि सदाशिव कौतुक रहेंगे। सरस्वती वंदना सुजाता देशपांडे तथा संचालन अर्चना मंडलोई करेंगी।

'आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती में सीआईटीएस की अनिवार्यता क्यों नहीं'

जबलपुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) को अनिवार्य योग्यता नहीं बनाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) और कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रशिक्षण अधिकारी जैसे पद के लिए सीआईटीएस को अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। छतरपुर निवासी सिपाही लाल अहिरवार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राहुल सिंह ठाकुर, श्रेयश राज त्रिपाठी और माहित प्यासी ने पक्ष रखा। याचिका में उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार ने आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए सीआईटीएस अनिवार्य करने के संबंध में राज्यों को पत्र भेजा था। इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में सीआईटीएस को अनिवार्य किया गया है, जबकि मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती के लिए यह अनिवार्य योग्यता नहीं है। याचिका में इसी आधार पर मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया।

अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति और भर्ती नियमों में बदलाव संभव

राज्य स्थापना दिवस से पहले कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी एक नवंबर से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों से जुड़े कई लंबित मामलों में नीतिगत निर्णय ले सकती है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, सेवा शर्तों और आचरण नियमों में बदलाव के प्रस्तावों पर सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समान प्रकृति के पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय एक परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग सहित संबंधित विभागों को कर्मचारियों से जुड़े नीतिगत मामलों में जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि स्थापना दिवस से पहले सरकार कुछ मामलों में निर्णय लेकर लंबित प्रक्रियाओं को गति दे सकती है।

प्रदेश में लंबे समय से अनुकंपा नियुक्तियों के कई मामले लंबित हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने ७०० से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद दूसरे विभागों में ऐसे मामलों का निराकरण होना बाकी है। इसी तरह संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और नियमितीकरण को लेकर भी नीतिगत स्पष्टता की जरूरत है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित २०२३ की नीति को कई विभागों में अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। नीति के तहत ५० प्रतिशत पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा होती रही है। ऊर्जा विभाग ने करीब छह हजार पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरे विभागों में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर निर्णय लिया जाना बाकी है।

सीपीसीटी से प्रभावित पदोन्नति का मामला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी की अनिवार्यता एक बड़ी अड़चन बनकर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने के बाद सीपीसीटी की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण पदावनत तक किया गया है। ऐसे मामलों को देखते हुए सीपीसीटी की अनिवार्यता में बदलाव या छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में सीपीसीटी को अनिवार्य नहीं रखा जाए।

पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में छूट संभव

पदोन्नति के नियमों में पात्रता अवधि को लेकर भी बदलाव की संभावना है। वर्तमान में कई संवर्गों में पदोन्नति के लिए पांच वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है। प्रस्तावित बदलाव में कुछ परिस्थितियों में इस अवधि में छूट देकर कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर देने पर विचार किया जा रहा है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जिनकी पदोन्नति प्रक्रिया निर्धारित सेवा अवधि के कारण अटकी हुई है।

भर्ती में बार-बार परीक्षा से राहत की तैयारी

सरकार भर्ती प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत समान प्रकृति के पदों के लिए अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय एक साझा परीक्षा कराई जा सकती है। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने की जरूरत कम करना और भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय व सरकारी संसाधनों की बचत करना है। भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन को लेकर संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

अनुकंपा नियुक्ति खत्म होने के मामले ने बढ़ाई मांग

सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक मामला भी कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा में है। विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारी अनीता विश्वकर्मा को जून २०२१ में अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी गई थी कि वे तीन वर्ष के भीतर सीपीसीटी उत्तीर्ण करेंगी। उन्होंने इस अवधि में कंप्यूटर डिप्लोमा किया, लेकिन सीपीसीटी उत्तीर्ण नहीं कर सकीं। चार बार परीक्षा देने के बावजूद सफल नहीं होने के बाद विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

स्थापना दिवस से पहले फैसलों पर नजर

कर्मचारियों से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। ऐसे में स्थापना दिवस से पहले सरकार की ओर से होने वाली बैठकों और प्रस्तावों पर कर्मचारी संगठनों की नजर है। हालांकि प्रस्तावित बदलावों में से किन मामलों पर अंतिम निर्णय होगा, यह संबंधित विभागों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

व्हाट्सएप पर दोस्ती कर तीन लाख हड़पे, क्रिप्टोकरेंसी का दिया झांसा

इन्दौर (एजेंसी)। व्हाट्सएप के जरिए बने दोस्त ने क्रिप्टोकरेंसी देने के नाम पर अपने दोस्त से ३ लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। पीड़ित दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है और व्हाट्सएप पर दोस्त बनें आरोपियों ने पहले अपने दोस्त को १० लाख रुपए की यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) ट्रांसफर कर उसका भरोसा जीता था। इसके बाद ३ लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी देने का झांसा देकर नकद रुपए ले लिए और फिर सम्पर्क तोड लिया।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सुनील चौधरी ने अपनी दर्ज शिकायत में बताया कि वह आरोपी प्रदीप बुक्कड़ को करीब तीन महीने से जानता है उससे उसकी पहचान वॉट्सऐप के जरिए हुई थी। सितंबर २०२५ में प्रदीप ने विक्की शर्मा से परिचय करा १० लाख रुपए की यूएसडीटी दी थी। क्रिप्टोकरेंसी मिलने के बाद उसे उन दोनों पर भरोसा हो गया था जिसके बाद २५ सितंबर को दोनों से वॉट्सऐप कॉल पर बातचीत हुई इस दौरान उन्होंने उससे कहा कि वे उसे ३ लाख रुपए की क्रिप्टोकरेंसी दे देंगे और उसे दशहरा मैदान बुलाया।

गांधी जयंती से नौ दिन चलेगा सेवा और स्वच्छता अभियान

आज से १० तक स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण और जरूरतमंदों की मदद पर जोर

भोपाल (एजेंसी)। गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में २ से १० अक्टूबर तक 'सेवा मेरा योगदान' अभियान चलाया जाएगा। नौ दिन के इस अभियान में जिला, विकासखंड, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की सेवा, सैनिक परिवारों का सम्मान और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद को भी शामिल किया गया है।

अभियान की शुरुआत २ अक्टूबर को स्वच्छता कर्मियों के सम्मान, प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प और जागरूकता रैली से होगी। जल स्रोतों, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान किया जाएगा। लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग करने तथा वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी।

स्वास्थ्य शिविरों में जांच और दवाओं की व्यवस्था

३ अक्टूबर को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें लोगों की स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और जरूरत के अनुसार दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। ४ अक्टूबर को वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में विशेष कार्यक्रम होंगे। वृद्धजनों के साथ संवाद, भोजन, फल और दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण किया जाएगा। अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते-चप्पल और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य जांच और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित होंगी।

जरूरतमंदों को चश्मे और दिव्यांगों को सहायक उपकरण

६ अक्टूबर को नेत्र परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। जरूरतमंद लोगों को चश्मे उपलब्ध कराने के साथ गंभीर मामलों में उपचार के लिए सहयोग किया जाएगा। ८ अक्टूबर को दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर रहेगा।

पौधरोपण के साथ सैनिक परिवारों का सम्मान

९ अक्टूबर को 'एक पेड़ मां के नाम', 'एक व्यक्ति-एक पौधा' और 'एक परिवार-एक पौधा' जैसी पहल के तहत पौधरोपण किया जाएगा। इसी दिन सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान भी किया जाएगा। अभियान के अंतिम दिन १० अक्टूबर को जरूरतमंद विद्यार्थियों को बैग, पुस्तकें, कॉपियां, स्टेशनरी, गणवेश और जूते उपलब्ध कराने के कार्यक्रम होंगे। इस तरह नौ दिनों तक चलने वाले अभियान में स्वच्छता गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है। राज्यों से लेकर स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कर्मयोगी सम्मान से डा. अशोक भार्गव सम्मानित

इन्दौर (एजेंसी) राज्यसभा सांसद संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज और स्वतंत्रता सेनानी प्रेमनारायण नागर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित एक सम्मान समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मयोगी सम्मान से अलंकृत कर समाजसेवी डॉ. कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ स्मृति सम्मान-२०२६ प्रदान किया गया। समारोह में कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र, पूर्व जस्टिस अनिल वर्मा और रंगकर्मी सतीश दवे को भी सम्मानित किया गया।

हीरानगर थाना प्रभारी निलंबित, विभागीय काररवाई का दिया हवाला

इन्दौर (एजेंसी)। मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों को नकली प्लास्टर चढ़ाने के मामले में आलोचना झेल रहे हीरानगर नगर थाने के प्रभारी सुशील पटेल को विभागीय जांच के चलते अधिकारियों ने कार्रवाई कर निलंबित कर दिया है। आरोपियों के इस नकली प्लास्टर चढ़ाने के वीडियो भी सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हुए थे जिसके बाद से हीरा नगर थाना लगातार आलोचना झेल रहा था वहीं इसके पहले भी इस थाना पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ पुलिस अधिकारियों को कई लोगों ने शिकायतें की थी। थाना प्रभारी पटेल के इस निलंबन आदेश के बारे में जानकारी अनुसार थाना प्रभारी में कार्य कुशलता की कमी और उन पर विभागीय जांच होने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी भी थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने की पुष्टि तो कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई की मुख्य वजह का जिक्र नहीं करते विभागीय कार्रवाई बता रहे हैं। बता दें कि विगत दिनों मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों को हीरानगर थाना पुलिसकर्मी जेल दाखिल कराने पहुंचे थे तब का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जेल के बाहर पुलिसकर्मी के साथ खड़े आरोपियों ने खुद अपने हाथ से नकली प्लास्टर उतार कर फेंका। जिसके बाद इन्दौर पुलिस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था।मामले में उच्च अधिकारियों ने हीरानगर थाना प्रभारी और स्टाफ से घंटों पूछताछ की थी। अब यह कार्रवाई हुई है।

हत्या के आरोपित दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

कोर्ट ने टिप्पणी की कि आज युवा वर्ग में संयम समाप्त हो रहा है

इन्दौर (एजेंसी)। न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की कोर्ट ने हत्या के एक प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी सगे भाइयों राहुल गिरगुने और रोहित गिरगुने पिता मानिकराव गिरगुने को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी रास्ता रोककर खड़े थे इस दौरान युवक आशुतोष द्वारा निकलने के लिए रास्ता मांगने की बात पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। घटना २ अक्टूबर २०२० की है। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह विशेष टिप्पणी की कि आज युवा वर्ग में संयम समाप्त हो रहा है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश जायसवाल के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले में मृतक का आरोपितों से कोई पुराना विवाद नहीं था। आरोपित घर के सामने कार पर केक रखकर खा रहे थे, जिससे सड़क अवरुद्ध हो रही थी। मृतक आशुतोष वहां से निकला और उसने रास्ता देने की बात कही थी। बस इतनी सी बात पर आरोपितों ने बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर दिया और उसके चाकू से गोदकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि घायल होने के बावजूद आशुतोष ने हिम्मत दिखाई और वाहन चलाकर अस्पताल तक पहुंच गया था लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि इस एक घटना ने कई परिवारों का जीवन नष्ट कर दिया। अगर आशुतोष को रास्ता दे दिया जाता तो आज वह जीवित होता और परिवार के साथ सकुशल जीवन जी रहा होता। हत्यारों ने एक परिवार से उनका वृद्धावस्था का सहारा छीनकर उन्हें बेसहारा कर दिया।

तालाब से पांच किमी तक निर्माण पर पाबंदी, नजदीक बने सरकारी परिसरों पर सवाल

अब बड़े सरकारी परिसरों के निर्माण और जल निकासी के असर का आकलन भी जरूरी

भोपाल (एजेंसी)। बड़े तालाब के कैचमेंट को बचाने के लिए मास्टर प्लान-२०४७ के ड्राफ्ट में रातीबड़, नीलबड़ और फंदा से सीहोर सीमा की ओर करीब पांच किलोमीटर तक निर्माण पर पाबंदियां प्रस्तावित की गई हैं। इसका आधार सेप्ट, अहमदाबाद की २०१५ की रिपोर्ट को बनाया गया है। रिपोर्ट में बड़े तालाब का कैचमेंट करीब ३६१ वर्ग किलोमीटर माना गया है, जो सीहोर जिले तक फैला हुआ है।

ड्राफ्ट में प्राकृतिक जल बहाव और बारिश के पानी के तालाब तक पहुंचने को देखते हुए कैचमेंट क्षेत्र की दूर स्थित निजी जमीन पर भी निर्माण को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। इसके बदले ग्रीन टीडीआर जैसे विकल्प देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी कैचमेंट में तालाब से करीब ७०० मीटर की दूरी पर कई बड़े सरकारी और संस्थागत परिसर विकसित हो चुके हैं। ऐसे में अब सवाल इन परिसरों के निर्माण से जल निकासी और प्राकृतिक जल प्रवाह पर पडऩे वाले असर को लेकर भी उठ रहा है।

२७५ से ३३० एकड़ में फैले बड़े परिसर

कैचमेंट क्षेत्र में भारतीय खेल प्राधिकरण, मप्र राज्य घुड़सवारी अकादमी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे संस्थान विकसित हैं। इन परिसरों का कुल क्षेत्रफल करीब २७५ से ३३० एकड़ बताया जा रहा है। इनमें सिर्फ भवन ही नहीं, बल्कि स्टेडियम, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, सडक़ें, पार्किंग और अन्य पक्की सतहें भी हैं। ऐसे में कैचमेंट संरक्षण के नए नियमों के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि निर्माण का आकलन केवल कुल जमीन के मुकाबले बने क्षेत्र के आधार पर होगा या बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव और जल निकासी पर पडऩे वाले प्रभाव को भी मापा जाएगा।

निजी जमीन पर सख्ती, सरकारी परिसरों पर अलग स्थिति?

मास्टर प्लान के प्रस्तावों में प्राकृतिक ढाल और जल बहाव को निर्माण नियंत्रण का आधार माना गया है। इसका सीधा असर कैचमेंट में आने वाली निजी जमीन पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर, इसी जलग्रहण क्षेत्र में पहले से विकसित बड़े संस्थानों के मामले में मौजूदा निर्माण और भविष्य के विस्तार के लिए अलग-अलग मानदंडों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि मास्टर प्लान में कैचमेंट संरक्षण के साथ पहले से विकसित परिसरों की स्थिति को भी स्पष्ट करना जरूरी माना जा रहा है। खासकर यह देखना होगा कि इन परिसरों में कितनी जमीन खुली है, कितनी पक्की है और बारिश का पानी किस तरह प्राकृतिक जल निकासी तंत्र तक पहुंचता है।

पुराने मास्टर प्लान में भी था कैचमेंट

बड़े तालाब का कैचमेंट पुराने मास्टर प्लान में भी चिह्नित किया गया था। नए ड्राफ्ट में सेप्ट, अहमदाबाद की २०१५ की रिपोर्ट को आधार बनाकर कैचमेंट का विस्तृत दायरा तय किया गया है। टीएंडसीपी कमिश्नर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक पहले से बने सरकारी संस्थानों में उपलब्ध जमीन की तुलना में निर्माण क्षेत्र कम है।

उन्होंने कहा कि टीएंडसीपी एक्ट के तहत शासन को समय की जरूरत के अनुसार मास्टर प्लान में संशोधन करने का अधिकार भी है। अब मास्टर प्लान-२०४७ के अंतिम स्वरूप में यह स्पष्ट होना अहम होगा कि कैचमेंट संरक्षण के नियम नई निजी कॉलोनियों और पुराने सरकारी परिसरों पर किस तरह लागू होंगे, ताकि प्राकृतिक जल प्रवाह की सुरक्षा का उद्देश्य समान मानकों के साथ पूरा किया जा सके।

भारत भवन में भावसार की कला-परंपरा के रंग शिष्यों के कैनवास पर दिखे विविध आयाम

भारत भवन में रूपाभ श्रृंखला के तहत प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन

भोपाल (एजेंसी)। भारत भवन की रंगदर्शनी दीर्घा मंगलवार को रंग, रेखा, रूप और भावों के ऐसे संगम की साक्षी बनी, जहां प्रख्यात कलागुरु लक्ष्मीनारायण भावसार की कला-परंपरा उनके शिष्यों के कैनवास पर अलग-अलग रंग-संवेदनाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ आकार लेती दिखाई दी। समकालीन कला को मंच प्रदान करने वाली प्रदर्शनी श्रृंखला 'रुपाभ' के अंतर्गत आयोजित इस समूह चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया।

प्रदर्शनी में भावसार के शिष्यों की विविध शैलियों और कला-दृष्टि से परिचित कराने वाली कुल ४० कृतियां प्रदर्शित की गई हैं। कला प्रेमियों के लिए यह प्रदर्शनी ४ अक्टूबर तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में शीला गर्ग, आलोक भावसार, राजू राठौर, वंदना शर्मा, निलेश उपाध्याय, शैलेन्द्र नामदेव, शंकर राजपूत, रविन्द्र भावसार, कल्पित सोनी और आदित्य भावसार की कृतियां शामिल हैं।

इन चित्रों में कहीं प्रकृति की सहज लय है तो कहीं मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म संसार। कहीं लोक संस्कृति रंगों में मुखर होती है तो कहीं आध्यात्मिक अनुभूति अमूर्त रूपों और प्रतीकों के माध्यम से कैनवास पर उतरती है।

उद्घाटन अवसर पर भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में गुरु-शिष्य परंपरा, स्मृति, प्रकृति, लोक संस्कृति और समकालीन संवेदना एक साथ रंगों के माध्यम से आकार लेती दिखाई देती है।

छह महीने से आयुष्मान योजना का भुगतान अटका

सड़क पर उतरे निजी अस्पताल संचालक, बोले- एनएबीएच की शर्त हटाओ

भोपाल (एजेंसी)। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कर रहे निजी अस्पतालों का भुगतान अटकने और अस्पतालों में एनएबीएच की अनिवार्यता के विरोध में बुधवार को निजी अस्पताल संचालक और डॉक्टर सडक़ पर उतर आए। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी जेपी अस्पताल परिसर स्थित आयुष्मान योजना के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। अस्पताल संचालकों ने पुराना बकाया भुगतान तत्काल जारी करने और एनएबीएच की अनिवार्यता हटाने की मांग की। अस्पताल संचालकों का कहना है कि कई अस्पतालों को पिछले पांच से छह महीने से नियमित भुगतान नहीं मिला है। कुछ अस्पतालों में इससे भी पुरानी राशि अटकी हुई है। भुगतान नहीं होने से दवा विक्रेताओं, कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रदाताओं का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है। उनका कहना है कि कई अस्पतालों पर औसतन डेढ़ से दो करोड़ रुपये तक की राशि बकाया है। भुगतान नहीं मिलने से अस्पताल संचालकों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। डॉ. अंजन पाराशर ने कहा कि अस्पतालों और योजना के बीच हुए समझौते के अनुसार केस का भुगतान ४५ दिन में होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में भुगतान लगातार टुकड़ों में मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जनवरी में १०० रुपये का काम होने पर २० रुपये और फरवरी में १०० रुपये के काम पर २० रुपये का भुगतान किया गया। इससे लंबित राशि लगातार बढ़ रही है। उनके अनुसार कई अस्पताल संचालकों ने कर्ज लेकर अस्पताल खड़े किए हैं। भुगतान अटकने से ऋण की किस्त, कर्मचारियों का वेतन और दवा-दुकानदारों का भुगतान तक प्रभावित हो रहा है।

एनएबीएच की अनिवार्यता पर भी विरोध

निजी अस्पताल संचालकों ने आयुष्मान योजना में एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) की अनिवार्यता का भी विरोध किया। उनका कहना है कि गुणवत्ता मानकों का विरोध नहीं है, लेकिन छोटे और मध्यम अस्पतालों पर एनएबीएच की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है। डॉ. अंजन पाराशर ने दावा किया कि एनएबीएच प्रक्रिया में अस्पतालों को २५ से ३० लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उनका कहना है कि जब पुराने भुगतान ही लंबित हैं, ऐसे समय में अस्पतालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना मुश्किल है। अस्पताल संचालकों के अनुसार एनएबीएच की शर्त पूरी नहीं कर पाने वाले छोटे और मध्यम अस्पतालों के आयुष्मान योजना से बाहर होने की आशंका है। इससे उन मरीजों पर असर पड़ सकता है, जो घर के नजदीक निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस उपचार कराते हैं।

एक अक्टूबर से डी-एम्पैनलमेंट की आशंका

डॉ धनजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बड़ी संख्या में अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-एम्पैनल किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

हालांकि, इस संबंध में संबंधित अस्पतालों की अंतिम आधिकारिक सूची या आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

संचालकों का कहना है कि यदि बड़ी संख्या में अस्पताल योजना से बाहर होते हैं तो सरकारी और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों पर आयुष्मान मरीजों का अतिरिक्त भार बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी बड़े स्तर की कार्रवाई से पहले अस्पताल संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।

डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे ८ कर्मचारी

जबलपुर (एजेंसी)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी दस्तावेजोंके माध्यम से डाक विभाग के विभिन्न पदों पर नौकरी करने वाले ८ कर्मचारियों के खिलापफ जांच आरंभ कर दी है। डाक ?वभाग ने इन सभी के दस्तावेजल जांच में पफजी पाए थे जिसके बाद इन सभी की सेवा समात कर दी है। सीबीआई दल ने इनमें से ५ आरोपियों को जबलपुर और ३ को कटनी से पकड़ा है। सीबीआई टीम की जांच चल रही है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कथित तौर पर फर्जी १०वीं की अंकसूची लगाकर नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दल के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जांच में फिलहाल आठ अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं, जबकि ३० से अधिक संदिग्ध नियुक्तियां भी जांच के दायरे में है। दल के मुताबिक डाक विभाग में नियुक्त अभ्यर्थियों की १०वीं की अंकसूचियों का संबंधित शैक्षणिक बोर्डों से सत्यापन कराया गया था।

जिसका ओटला है, वह तय करेगा किसकी लगेगी दुकान

सौ साल पुरानी सराफा चाट चौपाटी विवाद : निगम का आदेश असंवैधानिक करार

इन्दौर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ ने इन्दौर सराफा चौपाटी पर रात को लगने वाली दुकानों के बहुचर्चित विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई उपरांत में निगम के सराफा चौपाटी पर ८० चुनिंदा दुक